

श्री ना० कृ० शंजवलकर (मध्य प्रदेश) :
उपसभापति जी, मैं आपकी आज्ञा से निम्न-
लिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूँ :—

“यह सभा राष्ट्रपति से मिफारिश करती है
कि राष्ट्रपति द्वारा 18 जनवरी, 1973 को
संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन
आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में जारी की
गई उद्घोषणा को प्रतिसहरण किया जाये।”

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You
may speak after lunch.

The House stands adjourned till 2
P.M.

The House then adjourned
for lunch at fifty seven mi-
nutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch
at two of the clock, MR. DEPUTY
CHAIRMAN in the Chair.

I. MOTION RE. REVOCATION OF THE PROCLAMATION ISSUED BY THE PRESIDENT IN RELA- TION TO THE STATE OF ANDHRA PRADESH.

II. GOVERNMENT RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF THE PROCLAMATION ISSUED BY THE PRESIDENT IN RELATION TO THE STATE OF ANDHRA PRADESH

SHRI N. K. SHEJWALKAR
(Madhya Pradesh): Sir, I move:

“That this House recommends to
the President that the Proclama-
tion issued by the President on the
18th January, 1973, under article
356 of the Constitution, in relation
to the State of Andhra Pradesh, be
revoked.”

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय
के सम्बन्ध में चर्चा होने जा रही है, वह आज
अपने देश की बहुत प्रमुख समस्याओं में से
है और हो सकता है कि इसके सम्बन्ध में जो
भी निर्णय लिए जाएंगे उनका बहुत दूरगामी
परिणाम होगा। मैं पूर्व में भी एक बार आन्ध्र
प्रदेश के कुछ क्षेत्र में जाकर आया हूँ और
अभी हाल में पुनः आन्ध्र प्रदेश के पश्चिमी

किनारे की तरफ भी गया हूँ, उसके पर्याप्त
स्थानों पर जाकर आया हूँ। मैंने अनुभव
किया है कि वहाँ एक भी व्यक्ति प्रगट रूप
में ऐसा कहने हुए दिखाई नहीं देता जो
इन्टीग्रेशन के पक्ष में हो और तेलंगाना और
आन्ध्र दोनों को साथ-साथ रखने के पक्ष में
हो, यहाँ तक कि रात के 11—साढ़े 11 बजे
तक भी हजारों की तादाद में लोग इन्तजार
करते रहे और वे जानना चाहते थे कि संसद्
से जो व्यक्ति आया है, दिल्ली में उसकी क्या
प्रतिक्रिया है। एलूरु, अमलापुरम, राजमहेन्द्री,
सामरल-कोटा, काकीनाडा, रामचन्द्रपुरम,
एलामंचली, अनकापल्ली, विशाखापत्तनम और
विजयनगरम इन स्थानों के लोगों से मैं प्रत्यक्ष
मिल कर आ रहा हूँ। वहाँ की जनता में
क्षोभ भी है और खेद भी है कि इस जन-
आन्दोलन पर अकारण दोष मढ़ने की जो
क्रिया चल रही है, वह अच्छी बात नहीं है।
वास्तव में समस्या का हल क्या निकला
इसकी चर्चा करने के पहले थोड़ा इसके संक्षेप
में इतिहास को देख लेना जरूरी है। श्रीमन्
इस वर्तमान आन्ध्र प्रदेश में 21 जिले में, उन
21 जिलों में से 12 जिले ऐसे हैं जो नान-
तेलंगाना क्षेत्र के हैं और 9 भूतपूर्व हैदराबाद
रियासत के जिले हैं, जिसके लिए अलग तेलंगाना
की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने
3-10-72 को मुल्की रूल के सम्बन्ध में जो
निर्णय दिया, उसके बाद यह समस्या फिर से
जोर पकड़ चुकी है। वैसे तो मैं पूरे इतिहास में
नहीं जाता, किन्तु पृथक् तेलंगाना की मांग मैं
समझता हूँ कि उसी समय से शुरू हो गई थी
जिस समय आन्ध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था।
यह बड़े खेद की बात है कि पिछले 16 वर्षों के
भीतर भी लोगों के अन्दर एक
दूसरे के प्रति जिस प्रकार का
विश्वास उत्पन्न होना चाहिए, दोनों क्षेत्रों
की जनता में वह विश्वास नहीं उत्पन्न हो पाया
मुल्की रूल का एक बड़ा भारी बवडर,
भारी झगड़ा खड़ा हो गया। उसके 3-10-
72 के निर्णय के बाद स्थान स्थान पर उसकी
भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएँ हुईं। हैदराबाद

[Shri N. K. Shejwalkar.]

और तेलंगाना का जो भाग था वह भी इसके पक्ष में नहीं था। जो कुछ हुआ है उसमें उनके लिए हितकर है या नहीं, उसके बारे में उनको स्पष्ट ज्ञान नहीं था विशेष कर जबकि प्रधान मंत्री जी ने अपने 5 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा 27-11-72 को की तो उनके कारण और भी समस्या उत्पन्न हुई। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एलूरु में जहाँ मैं अभी जाकर आया, 25-10-72 को एक बड़ा भारी सम्मेलन हुआ था विद्यार्थियों और जनता की ओर से, जिसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री भी सम्मिलित हुए थे, लेकिन वह लोगों का समाधान नहीं कर सके और फिर उसके बाद नया जो ऐजिटेशन आज वहाँ हो रहा है, उसकी शुरुआत वहाँ से होती है। कल मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि लोक सभा में उस सम्बन्ध में चर्चा जो चल रही थी उसके बारे में कुछ सुनूँ। यह कहा जाता है कि यह जनतंत्र के तत्वों के विपरीत है और इस प्रकार की जो हिंसात्मक कार्यवाहियाँ वहाँ हुई हैं उनके बारे में विचार ठीक समझ कर करना चाहिये। मेरा ऐसा निवेदन है कि शायद इसमें कुछ अप्रचार भी है, हिंसा को कोई भी बढ़ावा नहीं देना चाहता। लेकिन हिंसा कौन कर रहा है, कि कारण किससे हिंसा हुई है, इसके बारे में भी मैं आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करूँगा (Interruptions) जैसा यहाँ भी कहने में आ रहा है कि जनसघ के लोग भी उसमें सम्मिलित हैं, मैं बताऊँगा कि कौन इसमें शामिल है। मैं सब प्रमाण लाया हूँ और सदन के सामने वह प्रस्तुत करने वाला हूँ।

सबसे पहले शांतिपूर्ण आन्दोलन की शुरुआत 21-11-72 को हुई, जिस दिन पूरे प्रदेश के अन्दर, आंध्र प्रदेश के भाग के अन्दर बन्द की घोषणा की गई और उस दिन वहाँ वन्द हुआ। लेकिन कुछ स्थानों पर उस दिन गोली चलाई गयी और वह अकारण, अधिक शक्ति का प्रयोग था, अपनी शक्ति का दुरुपयोग था। यह बात मिरसापुर के बारे

एसोसियेशन ने एक अभिभावक की जो कमेटी बनाई थी तीन स्थानों पर जो एक प्रकार की एक्सेस हुई उनके सम्बन्ध में उन्होंने जो कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। मैं उसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। एक स्थान पर जैसा कि अभी मेरे एक मित्र ने कहा वायलेस हुआ उसके लिए कौन उत्तरदायी था। मैं भूपेश मुत्त जी को बताना चाहता हूँ कि राजमुंदरी में जो कुछ हुआ उसके सम्बन्ध में मेरे पास चार सुफा की रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने बताया है कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी ने उत्पात मचाने की कोशिश की है। पता नहीं सरकार के पास इस सम्बन्ध में जानकारी है या नहीं और अगर जानकारी है तो क्या करना चाहती है।

यह वर्तमान जो आन्दोलन चल रहा है, इसका जो ट्रेड है, आगे जिस तरफ यह जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर जनतंत्र में आप किस प्रकार के आन्दोलनों की अपेक्षा करते हैं। जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी जिन्दा रहे तो डेमोक्रेसी को जिन्दा रखने का काम खुद सरकार का भी है। जब जनता कोई मांग उपस्थित करती है जो उसके ऊपर शीघ्रातिशीघ्र विचार करना शासन का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। आज देखने में यह आता है कि जब कहीं कोई इस प्रकार का आन्दोलन उठता है तो उससे पहले शासन उस पर ध्यान नहीं देता है। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगता है तब शासन ऐसी कार्यवाही करने लगता है जिससे स्थिति और गम्भीर हो जाती है।

श्रीमन, मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बिलासपुर में जो रेलवे के कर्मचारी हैं वे बहुत दिनों से कुछ मांगे करते चले आ रहे थे, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी गईं। जब उन्होंने रेल रोकना आरम्भ कर दिया तब उन पर गोली चल गई, लेकिन उनकी मांगें भी तुरन्त मान ली गईं। यदि पहले उनकी मांगें मान ली जाती तो शायद इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न

नहीं होती। यही स्थिति हर मामले में देखने में आती है। सरकार सबसे कोआपरेशन की मांग करती है। खुद प्रधान मंत्री जी ने यहाँ सदन में कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि सारे विरोधी पक्ष के लोग और सारे ससद सदस्य राष्ट्र की समस्याएँ हल करने में सहयोग करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनको “इर्रेस्पॉन्सिबिल” शब्द का प्रयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। जनसभ ने जो प्रस्ताव किया कि दुबारा स्टेट्स रिआर्गैना-इजेशन कमीशन बनाया जाय, उसको उन्होंने इर्रेस्पॉन्सिबिल कह दिया। यदि इस सम्बन्ध में उनके पास कोई तर्क था तो उसको वे प्रस्तुत करती, लेकिन ऐसा न करके “इर्रेस्पॉन्सिबिल” शब्द का प्रयोग करना कहाँ तक उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का द्योतक है, इसका श्रीमन्, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। यह कोई नई मांग नहीं थी। चार वर्ष पूर्व जो हमारा अधिवेशन हुआ था उसमें भी यह मांग रखी गई थी। यदि स्टेट्स रिआर्गैनाइजेशन कमीशन का गठन हो तो जनता में इस सम्बन्ध में जो भावनाएँ हैं उनको सुनने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। न कि जो है किसी को सुने वगैरह यहाँ स्टेट-मेट दे देना कि हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं नहीं समझता कि यह तरीका ठीक है। जिसको लीगल पैलेसी कहते हैं, इसी तरह की प्रजातन्त्र में एक यह पैलेसी है और यह स्वाभाविक है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि पार्लियामेंट निर्णय करती है और उस में एक बहुमत दल होता है, उस का निर्णय होता है, लेकिन उस बहुमत दल में भी कुछ लोगों का निर्णय ही सामने आता है और उस के अधीन ही सारी कार्यवाही की जाती है। कल चर्चा के समय एक बात सामने आयी कि यदि प्रधान मंत्री संतुष्ट हो जाय तो भी एक कविसिंग आर्ग्यूमेंट सामने आना चाहिए। कविसिंग आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए आप तैयार हैं क्या? मैं दे सकता हूँ और मैं उसे प्रस्तुत करूँगा। मेरे पास वह है, लेकिन कभी आप ने कविसिंग आर्ग्यूमेंट सुनने का प्रयास किया है। यह बात आज

पैदा हो गयी कविसिंग आर्ग्यूमेंट की, लेकिन जब आपने 5 सूत्री कार्यक्रम जबरदस्ती रखा था तो क्या आप ने उनसे यह बात पूछी थी। इस की जिम्मेदारी किस पर है? मैं आपको बतलाऊँगा कि इस का इतिहास देखने से आपको पता लगेगा कि आखिर यह मांग जो है वह किसी एक प्रान्त को दो प्रान्त करने की मांग नहीं है, यह वास्तव में उनको पहले जो एक करने की कोशिश थी वह आज नाकामयाब हो गयी है और उन को केवल पूर्व परिस्थिति में लाने का प्रश्न है। क्या यह नये सिरे से कोई विभाजन है, ऐसा विचार करना ही मैं समझता हूँ कि गलत दिशा में विचार करना होगा।

सब से पहले मैं जो इसका इतिहास है भाषा-वार प्रान्त रचना का, उसके सबध में कुछ बतलाना चाहता हूँ। सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा 1908 में इसकी मांग की गयी थी और उन्होंने निजी रूप में बिहार और सिंध वगैरह को अलग-अलग करने का विचार कर लिया था और उसके आधार पर ही सोचना शुरू कर दिया था। यह सवाल उस समय में शुरू हुआ है। 1947 में जब भारत स्वतन्त्र हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने अपने जो विचार इस सबध में प्रदर्शित किये थे वह इस प्रकार थे :

“First things must come first and the first thing is the security and stability of India.”

यानी उस वक्त उन्होंने इसको एक दम से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन 1948 में एक दर कमीशन इस सम्बन्ध में नियुक्त किया गया कि आंध्र, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के संबध में विचार प्रदर्शित किये जाय और यह विचार उन्होंने रखा। कमीशन ने जो रिपोर्ट दी 10 दिसम्बर, 1948 को, उसमें उन्होंने बताया कि :

“It strongly expresses itself against any reorganisation of provinces being under taken in the then

[Shri N K Shejwalkar]

prevailing circumstances It said that formation of provinces exclusively on linguistic considerations would be inadvisable It emphasized that homogeneity of language should enter into consideration only as a matter of administrative convenience "

तो यह दर कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने इस बात को रखा था कि यह जरूरी नहीं है कि लिग्विस्टिक बेसिस पर ही उनको बना दिया जाय और आगे उन्होंने स्पेमिफिक टेस्ट बताये कि

"Financial self-sufficiency, administrative convenience, capacity for future development and a large measure of agreement within its borders and among the peoples speaking the same language, care being taken that the new province should not be forced by the majority upon a substantial minority of people speaking the same language "

यह एक उसमें बहुत महत्व की बात है और तैलगाना के लोग जो अलग से माग करने चले आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन का कहना ठीक था । उस का आधार यह था कि जबरदस्ती दोनों को साथ रखने की कोशिश करने से तो कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

इसके बाद जयपुर में जो प्रेस कंसेशन हुआ दिसम्बर, 1948 को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री पट्टाभि सीतारमैया लिग्विस्टिक स्टेट्स के सिद्धांत के बारे में पुनर्विचार करने वाले थे, और उन्होंने जो विचार किया उसके बाद उनका निर्णय निम्न शब्दों में है

"When earlier the Congress had accepted the general principle of linguistic provinces it was not experienced with the practical implication of the principle The primary consideration of States' formation should be the security, unity

and economic prosperity of India Language was a binding force up to a point but a separating one thereafter The policy on linguistic provinces should be applied after careful thought had been given to each separate case "

इसके बाद फिर यह आन्ध्र का प्रश्न आया और आपको पता है कि पाटिट श्रीरामुल्लु ने वहां पर आमरण अनशन किया और 15 दिसम्बर, 1952 को उनका स्वर्गवास हो गया । इतना सारा वैकग्राउन्ड होने के बाद आन्ध्र प्रदेश का निर्माण हुआ । यह ध्यान में रखने वाली बात है कि उस समय यह हैदराबाद के जो जिले थे उसमें नहीं थे और उसके बाद 19 दिसम्बर 1953 को फिर से एस० आर सी० की उस वक्त में नियुक्ति हुई जिसके अध्यक्ष (चेयरमैन) श्री फजल अली थे और दूसरे सदस्यों में श्री कुजूरू और मिस्टर पाणिकर थे । कुजूरू साहब की अमी भी यह राय है कि इसका विभाजन कर दिया जाए, जिन्होंने उस समय भी अपनी राय प्रस्तुत की थी । कमीशन ने जो अपने निर्णय दिए हैं वे रिपोर्ट के पैराग्राफ 386 पर हैं । उसको मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उतना समय नहीं है, लेकिन मैं जो मिफारिश विशेष रूप से उन्होंने की है उसका उल्लेख समय मिलने पर आगे करूंगा । तैलगाना के संबंध में जब दोनों पक्षों का एग्रीमेंट हुआ उसके टर्म्स इस प्रकार के थे

"Telengana should have 40 per cent representation in the Cabinet The Central and general administrative expenditure was to be shared proportionately between the two areas The surplus of income over expenditure from Telengana area should be expended exclusively on the development of the Telengana area A regional council for Telengana should be established as a statutory body Future recruitment to Services would be on a population basis from both regions The arrangement was to subsist for five years and should be extended for

another five years if Telengana Members of the Assembly desired it."

यानी, प्रारम्भ से ही दोनों को अपनी सिक्योरिटी के बारे में एक दूसरे पर शक था और प्रायः ये सब बातें आपस में तय कर ली गई कि 40 प्रतिशत कैबिनेट में भी आर्येण और उसके बाद में फन्ड्स का भी डिस्ट्रिब्यूशन किस तरह से होगा, सर्विसेज में लोगों का परिमाण क्या रहेगा। उन सारी बातों को सामने रखा गया। अब इसके बाद आग का इतिहास शुरू हुआ। वहां जो भी आज तक मंत्रिमण्डल रहा वह जो आजकल का शासन करने वाला दल है, कांग्रेस, उसका मंत्रिमण्डल रहा। अब उन्हीं के अलग-अलग स्थानों में जो कुछ नेता लोग थे, उन्होंने वहां पर क्या किया या नहीं किया, उसका परिणाम मात्र यह हुआ कि एक दूसरे के प्रति शका बढ़ती चली गई और आज तक बजाए इसके कि वे नजदीक आते वे एक दूसरे से बिलकुल दूर होते चले गए और मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिवाय कुछ व्यापारियों को छोड़कर जो इसमें इन्टरेस्टेड थे कि एकाधिकार बना रहे तो उसमें व्यापारियों को लाभ मिले, व्यापारियों में भी जो इस प्रकार के वेस्टेड इन्टरेस्ट्स थे वह मूवमेंट के पक्ष में नहीं है, वे इस पक्ष में हैं कि इकट्ठा रहे, लेकिन बाकी सर्व साधारण लोग यह चाहते हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, और हम, दोनों क्षेत्रों की जनता के अलग-अलग प्रदेश बन जाये तो हम सुख की नीद सो मकने हैं और अपने भविष्य के बारे में कुछ निर्माण कर सकेंगे।

एम० आर० सी० ने पैराग्राफ 384 में और भी बताया कि :-

"The rational criteria recommended by the SRC for the reorganisation of States were to recognise linguistic homogeneity as an important factor conducive to administrative convenience and efficiency, but not to consider it an exclusive and binding principle, over-riding all other considerations, administrative, financial or political; to ensure that

communicational, educational and cultural needs of different language groups, whether resident in predominantly unilingual or composite administrative units, are adequately met."

यानी

"(c) where satisfactory conditions exist, and the balance of economic, political and administrative considerations favour composite States, to continue them with the necessary safeguards to ensure that all sections enjoy equal rights and opportunities;

"(d) to repudiate the 'homeland' concept, which negates one of the fundamental principles of the Indian Constitution, namely, equal opportunities and equal rights for all citizens throughout the length and breadth of the Union;"

यानी इस में इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि दो प्रकार के सिटीजनशिप का निर्माण न किया जाय, जिसमें किसी को तो एक प्रकार की सुविधा दी जाय और किसी को दूसरी सुविधा न दी जाय। यद्यपि मैं इस पक्ष का हूं कि अब ऐसी स्थिति है कि दोनों को स्वतन्त्र रूप में रहने दिया जाय। फिर भी मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि मुल्की नियमों को स्थायी बनाया जाय, क्योंकि इसके द्वारा दो प्रकार के सिटीजनों का निर्माण होता है। यह बात अच्छी नहीं है और इसके कारण वहां सारे क्षेत्र में अशांति बनी रहेगी। हां, अगर वास्तव में हमें आन्ध्र और तेलंगाना क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है और उसके लिए कोई बोर्ड स्थापित किया जाता है जो उस क्षेत्र के लिए विशेष सुविधा दे, विशेष राहत दे, तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। इस तरह की बात को उस क्षेत्र के लोगों को विचार करना है और फिर वे इस बारे में अपनी महमति दे सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो रायलसीमा का भी क्षेत्र है जो पिछड़ा! आ है और उसकी उन्नति करनी है तथा सुविधा भी देनी है। अगर इस तरह से सब क्षेत्र का एक कम्पोजिट युनिट बन जाय, तो इस आधार पर इस तरह की चीज का विचार किया जा

[Shri N. K. Shejwalkar]

सकता है। लेकिन यह बात कभी नहीं सोची गई कि पुरानी प्रथा जारी रखने के कारण ऊपर ऊपर से तो यह मालूम पड़ता था कि सब तरह की शांति है मगर भीतर कुछ बात थी। जिस प्रकार से कांच के गिलास में दरार पड़ जाती है और उसके टुकड़ों को दुबारा इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से दोनों क्षेत्रों को अब इकट्ठा करने की जो कोशिश की जा रही है, उस में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है।

जैसे सर्वविदित है कि एक रीजनल कमेटी बनी थी, उसके फंडस भी अलग हो गये थे और एडमिनिस्ट्रेशन में उनको स्टेट्यूटरी राइट्स एंजॉइन्मेंट करने के बारे में मिल गये थे। तेलंगाना के बारे में जो रीजनल कमेटी थी उसका एक विशेष अस्तित्व था। उसकी बात सुनी जाती थी और उसके आधार पर मंत्रालयों को निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ता था। यह सब होने के बाद भी यह समझा जाय कि वेअलग-अलग नहीं है? साथ-साथ है, तो मैं यह पूछना चाहता हू कि अब साथ-साथ क्या रहा? जब कमेटियां अलग-अलग हो गई, फंडस अलग हो गये, परिस्थितियां अलग-अलग हो गई, तो फिर कौन सी बात साथ रह गई है? अगर फिर भी उनको एक साथ रखा गया तो इसकी वजह से राष्ट्र के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जायगी। मैं समझता हू कि यह समस्या का सही आकलन नहीं है।

अब मैं इस सन्दर्भ में जो आज हमारे सामने समस्या है, जिस को वास्तव में एक विभाजन की समस्या माना जाता है और कभी भी यह कहा जाता है कि इसकी प्रतिक्रिया दूसरे प्रदेशों में भी हो सकती है। तो इन सारी बातों का विचार ठीक से किया जा सके और इसी लिए हम लोगों ने यह मांग की है कि इस सम्बन्ध में एक कमिशन बिठलाया जाय। आखिर यह नहीं हो सकता है कि अलग अलग बातों के लिए अलग-अलग मापदण्ड बनाये। अगर यह बात कहने है तो जनता को एक प्रकार से धोखा देते हैं। हर जगह की समस्या अलग है, इसलिये कोई एक नियम, एक

सिद्धान्त लागू नहीं किया जा सकता। जब महाराष्ट्र बनने का प्रश्न आया उस समय भी यह बात एडवोकेट की जाती रही है और जैसा मैंने इतिहास बताया है कांग्रेस के प्रमुख लोगों की, प्रधान मंत्री की क्या राय थी। यह मैंने बताया है। इसके बाद मैं हमने देखा है कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा आन्दोलन हुआ और वहां सैकड़ों लोग मारे गए और उसके बाद हुआ वही, महाराष्ट्र अलग बना, गुजरात अलग बना। आज मेघालय, हरियाणा सब तरफ इसी तरह का इतिहास है। किसी ने धमकी दी, हम प्राणाघात करेंगे, चाहे रामलु के स्वर्गवास के कारण घबड़ा गए और तारासिंह जी ने कहा कि हम जल मरेंगे उस आधार पर हरियाणा और पंजाब का विभाजन कर दिया गया।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : गलत है।

श्री ना० कृ० शंजवलकर : होगा गलत लेकिन उन आधार पर किया गया था।

श्री रणबीर सिंह : हरियाणा और पंजाब के लोग.

श्री ना० कृ० शंजवलकर : ठीक है, हरियाणा और पंजाब के लोग चाहते थे लेकिन पहल मना किया गया और बाद में माना गया। आज आन्ध्र प्रदेश के लोग खुशी से अलग होना चाहते हैं और तेलंगाना के लोग खुशी से अलग होना चाहते हैं। परिस्थिति सुधर सकती है, एक दूसरे मिल कर रह सकते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस के अन्दर इस सम्बन्ध में दो राय हैं और तेलंगाना एम० पीज ने कांग्रेस दल से इस्तीफा तक दे दिया। अब आपके पास कौनसा ऐसा टेस्ट है जिसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि वहां की जनता क्या चाहती है। मैं एक उदाहरण रखता हू। यहां गृह मंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री के रूप में नहीं, एक माधारण नागरिक के रूप में, अपनी आइडेंटिटी बताते हुए वे चलें, मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हू। आन्ध्र प्रदेश के किसी भी गांव में चने जाइए

मैं अभी देखकर आया हूँ, आप प्रश्न पूछ लीजिए, हा सफेद टोपी पहनकर जाएंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, वे समझेंगे कि कांग्रेस का नेता, है इस प्रकार का वातावरण वहाँ है। कांग्रेस और साम्यवादी लोगो का जो रवैया है उसके बारे में वहाँ नागजी है।

SHRI KOTA PUNNAIAH (Andhra Pradesh) May I know from the hon'ble Member how many villages in Andhra Pradesh he has visited?

SHRI N K SHEJWALKAR I have myself given a list of the villages I have visited

MR DEPUTY CHAIRMAN You have to conclude now, Mr Shejwalkar

श्री ना० कु० शेजवलकर मैं इसलिए यह कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने वह क्षेत्र देखा है, मुझे इस बात का गर्व नहीं है कि मैंने वह सब देखा है। आपको जनता की समस्या सचमुच समझनी है तो वहाँ चलिए। दो आदमियों को हैदराबाद भेजकर आप रिपोर्ट मंगा लेते हैं और बम्बई में एक स्टेटमेंट दे देते हैं या दिल्ली से आपके नेता कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। इसमें परिस्थिति मुघरने के बजाय बिगड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसका अध्ययन करें। आज यह कहा जाता है कि जब तक शांति स्थापित नहीं होगी तब तक हम विचार नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि शांति बिगाड़ी किसने है। वहाँ की जो परिस्थिति बनी उसमें पहले भूख हड़ताल, जुलूस, फिर बन्द, इन प्रकार एक-एक करके कदम उठाए गए, जनताविक डग से, प्रजाताविक डग से जितने कदम उठाए जा सकते थे वे सारे कदम उठाए गए, फिर भी वहाँ वायलेम का मामला नहीं है। आगने और लागो को बुलाया, जो आपके दल के जन-प्रतिनिधि हैं। वे कहते हैं कि इसीफा देगे लेकिन क्या हो गया, उनको आपने रोक रखा है, हो सका है कि वह गापको दन की दृष्टि से ठीक हो, लेकिन जो आन्दोलन चला

रहे हैं जनता की तरह से पहले से उन लोगो ने एन जी ओज ने, विद्यार्थियो ने, एडवोकेट्स ने और वहाँ के सारे व्यापारी लोगो ने एक समिति बनाई है और उस समिति के द्वारा जो-जो कदम उठाए गए जनता ने उनका पालन किया।

जिस दिन उन्होंने घोषणा की उसके बाद उन्होंने सारी कार्यवाहिया की। मैं जानता चाहता हूँ गृहमंत्री जी हमको बतलायें कि कांग्रेस के अन्दर इसको उन्होंने एक डोमेस्टिक एफेयर समझकर रखा है। मुख्य मंत्री जी से मिलने के लिये हम लोग गये थे। उन्होंने कहा था ज्यादा समस्या गंभीर नहीं है। आंध्र प्रदेश के लोगो की एक रीजनल कमेटी बना ली जाए तो वह मान जायेंगे। यह बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। नवम्बर के आखीर में या पहली दिसम्बर की तारीख होगी। लेकिन उनकी अपेक्षा के विपरीत वहाँ आन्दोलन चलता रहा और आज सौ दिन हो गये। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन दिनों में कोई कर्मचारी नौकरी पर नहीं गया, कोई अभिभावक अदालत में नहीं गया, कोई विद्यार्थी स्कूल में नहीं गया। जब से घोषणा की गई सरकारी कार्यालय और बाजार बन्द रहे। आप इसको भी जनता का आन्दोलन नहीं समझेंगे तो फिर किसको जनता का आन्दोलन समझेंगे? किमके आधार पर आपके जितने भी एम० एल० एज० या एम० पी० यह कह सकते हैं—आपकी डर की वजहसे हो सकता है—कि यह जनता का आन्दोलन नहीं है? अगर उन्होंने आपके डर की वजह से कहा तो उनसे आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर उनको खुद का कोई डिस्क्रिशन नहीं है तो यह जनता के प्रतिनिधि नहीं है।

The do not represent the people's wishes at all.

मैं दबाव तो मेरी तरफ और दूसरा दबाव दे तो उसका तरफ बोलते हैं, उसकी मानिक बात करते हैं तो वह धोखा देने वाले हैं

[श्री ना० कृ० शेजवलकर]

आपको इस सम्बन्ध में बताया कि वहा वास्तविक स्थिति ऐसी है कि एक-एक व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में चिन्ता हो गई है। उसके मन में गभीर स्थिति से उत्पन्न प्रश्न है कि हमारा भविष्य माथ में रहने में उज्ज्वल है या नहीं? इस सम्बन्ध में जो एप्रोच है वह उल्टा एप्रोच है। यह कह देना कि शान्ति जब होगी तब हम बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आग लग गई और हम कहेंगे कि हम पानी डालेंगे तब जब हम खाना खाकर तैयार हो जाएँ, जब हमको शान्ति हो जाएगी, उचित है। किस तरफ की शान्ति आप चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 8-10 दिनों में वान सी घटना हुई है? आप कितने दिन तक इस किस्म की शान्ति रखना चाहते हैं? कौन सी दुर्घटना पिछले 15 दिनों में हुई है, जिसके कारण आपको शान्ति का खतरा है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN Mr. Shejwalkar, you should wind up now. You cannot go on like this. This is the third time I am telling you.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: By quarter to three, I will finish.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, in two minutes you should wind up.

श्री ना० कृ० शेजवलकर I will try. मेरा निवेदन है कि वहा की समस्या का हल अगर कोई हो सकता है, तो केवल यही हल है कि आप दोनों को अलग-अलग खुशी से रहने दें। इसमें जितना विलम्ब होगा, जितनी देर आप करेंगे उतनी ही उसमें कठिनाई होगी। यह समझना भी गलत है कि इसका पोलिटिकल एक्सप्लायटेशन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पोलिटिकल कलर आपके शासन के द्वारा इसमें लाया जा रहा है क्योंकि जनसंघ का वहा कोई होल्ड नहीं है। वहां हम निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने के लिए गये थे, वहा अमेम्बली में जनसंघ का कोई सदस्य नहीं है। आज भी देखेंगे तो कोई जनसंघ

का एम० एन० ए० वहा जाकर बैठने वाला नहीं है। अगर आप प्रेसिडेंट रूल करके एसेम्बली डेजाल्व कर देते, दोबारा चुनाव कराते तो शायद यह बात समझ में आ सकती थी। अभी स्थिति ऐसी है कि आप उसका कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। आप उस समस्या को रख कर बैठे हुए हैं, उसके लिये विचार करने के लिये भी तैयार नहीं हैं।

तीन महीने हो गये उस समस्या को, कोई परिस्थिति नहीं बदली। मेरी समझ में इस प्रकार का प्रोक्लेमेशन निकालना यह सविधान का सही उपयोग नहीं है—मैं दुरुपयोग नहीं कर सकता—लेकिन यह सही उपयोग नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी सविधानिक कठिनाई क्या उत्पन्न हो गई। आपका वहा एक इलेक्ट्रेड हाउस था, सदस्य थे, वहां के मुख्य मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था। आपके ही लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, निर्णय नहीं ले सकते थे, ऐसी बात सामने नहीं आई। इससे कौन सी समस्या हल हुई। इससे कोई समस्या हल नहीं हुई, उल्टे इससे समस्या उलझी है।

(Time bell rings)

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आप समय दे नहीं रहे हैं, इस लिये मैं आपकी अनुमति से केवल कुछ डाक्यूमेंट्स सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरे पास राजमुंदरी की रिपोर्ट है जो कि वहां की सिटीजन्स ऐक्शन कमेटी ने प्रस्तुत की है। इसी प्रकार फायरिंग के बारे में वहां की बार एसोसिएशन ने एक इन्क्वायरी काडकट की। नरसापुर में जो...

श्री उपसभापति : वाद में आप उनको दे दीजिएगा।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : मैं इसलिए इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि इसके सम्बन्ध में विचार करके मन्त्री जी उत्तर दे सकें।

श्री उपसभापति : वाद में उनको दे दीजिएगा।

श्री ना० कृ० शंजवलकर : मैं सदन से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो प्रस्ताव है उसका सदन अनमोदन करे।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI UMASHANKAR DIKSHIT): Mr. Deputy Chairman, I rise to move—

“That this House approves the Proclamation issued by the President on the 18th January, 1973, under Article 356 of the Constitution, in relation to the State of Andhra Pradesh.”

Sir, this House is fully aware of the happenings in Andhra Pradesh, particularly after the Supreme Court judgment on the Mulki Rules. It is well known, every section of the House will agree, I hope, that till a day or two before the announcement of the judgment, calm prevailed all over Andhra Pradesh, in both regions or in all the regions of Andhra Pradesh. It was a settled Government. It was a stable and progressive Government. Several progressive measures had been taken, mostly unanimously. And in other respects the State was well settled for progressive development. Then, as you know, the Mulki Rules judgment came and it invalidated the Mulki Rules. Now, the question has to be understood in its correct perspective. Normally there would be no question of the Constitution providing or there being any gentlemen's agreement or any other special provision for providing special concessions or particular provisions for employment in the area for the local people or other such measures either in the matter of education or in the matter of employment or in the matter of promotions. It was because before the Constitution came into existence, certain rules were in existence in the Telengana region of Andhra Pradesh which, the Supreme Court finally found, had their own original validity which could not be taken away or made *non est*. So far as the subsequent position is concerned, as you know, the High Court in Andhra Pradesh has delivered another

judgment and it has given a new definition or has interpreted anew the provisions of the law in the matter of definition of a 'Mulki'.

As a result even a citizen born in Telengana now need not be considered as a Mulki and the Mulki Rules may not apply to him. There have been three judgments. The first judgment invalidated the Mulki Rules. The final judgment of the Supreme Court again validated or revalidated or declared as valid the Mulki Rules. Now the last judgment has given rise to a new controversy. That is that the very definition of Mulki Rules should be considered in a different sense.

As I was saying, after the Mulki Rules judgment for some time a certain amount of agitation took place became disturbed. The members of the became disturbed. The member of the Andhra legislature and particularly the Congress legislature party went into the matter in all the details. They made every possible effort to come together and to come to a settlement; but they failed. Finally the Congress legislature party took a decision and the Members of Parliament here and members of the Legislature there appealed to the Prime Minister to consider the situation on a broad basis and find a solution.

Our friend on the other side who has moved a counter motion said that as soon as a problem arises we should immediately come out with a solution so that the situation does not become worse. In this case action was taken soon and after discussion with all the interests concerned a formula was evolved. What did the formula mean? The formula was based on the scheme of the safeguards mutually agreed to in 1956 with only some marginal adjustments. That is how the five point formula was evolved. The Mulki Rules Act which incorporated on the five point formula regularises the appointments made since November 1956 of persons from Andhra region and non-Telengana people in the Telengana region. It also provided for the total repeal of

[Shri N. K. Shejwalkar]

reservations by the end of December 1977 in respect of posts in the twin cities and by the end of December 1980 in respect of posts in other parts of Telengana. The whole idea was to put a definite limit of time on the special provisions which really militate against the spirit of the Constitution which does not permit discrimination of any kind. One set of concessions comes to an end by the end of 1977 and the other by the end of 1980. As you know this Act had the effect of assuaging the feelings of the people. But this did not last long and there arose some misgivings over the effect of the five point formula and about the position of Andhra region citizens in the twin cities and so on. And, Sir, an agitation was started, a well-planned agitation. It is true that feelings had begun to run high and there was considerable emotional disturbance due to a lack of or inadequate understanding of the provisions of the new Act or of the formula. Sir, I have not gone on any tour of Andhra Pradesh and there were good reasons why I should not have gone there. It might have further added to the misgivings of the people. Their minds were so agitated that no appeal to reason would have really had any effect.

Sir, I submit with due respect to the other side that a very deliberate effort was made to take advantage of the misgivings and misunderstandings that arose in connection with the new formula and an agitation of a serious and explosive character, was started and, as you know, Sir, thereafter a large number of incidents have taken place. Lawlessness virtually stopped the Administration in the whole of Andhra region from functioning. Incidents of violence aimed at the railways and the other kinds of transport, resulted in huge loss of public property. In some parts the agitation caused deplorable loss of human lives, and it became impossible to allow this sort of thing to continue any longer. The Chief Minister's position was somewhat misunderstood mainly

because he hails from the Telengan region and even his innocent statements or his ordinary reactions to events were grossly misunderstood. Having found that it was not possible for him to control the administrative break-down in the Andhra region and having found that over a lakh of NGOs had struck work and in a large number of places the Government machinery had come to a halt, he considered it wise—and we should be thankful to the Chief Minister and his associates—that he should resign and so he quickly decided to submit his own resignation and the resignation of his Council in order to make it possible for the Presidential Administration to try and control the situation. It was not possible for the Chief Minister or his Government to make that kind of an effective impact on the situation which the Presidential Administration alone can make. Thereafter, Sir, as you know, the situation has been bit by bit brought under control.

Sir, it was said by the Member who moved the motion for revoking the Presidential Proclamation that the situation was so completely under control that he wondered why other measures or other steps were not being taken. That is a very well-deserved tribute, and a significant recognition and acknowledgement of the fact that the introduction of the President's Rule has well served its purpose.

SHRI BHUPESH GUPTA: Do not take it as a tribute. . .

SHRI UMASHANKAR DIKSHIT: I do not agree that everything has come completely to normal. I do not accept that position. But I do claim that the situation has been gradually and steadily improving. If you count the number of incidents, if you look to the general approach of the leaders and others, you will see that—and we have information to that effect—the attitude of Civil Surgeons, Assistant Civil Surgeons, N.G.Os. and others, is changing. Even the students feel now that the situation should be re-

considered. Some of them, Sir, are not sure whether the original stand they took was the right stand or not. I would not like to go into controversial matters. But what I would impress upon the House is this....

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh): This is primarily due to the fact that the Prime Minister has assured them that even separation is a matter which she is prepared to consider and that has pacified them.

SHRI UMASHANKAR DIKSHIT: There has been no such statement as Tyagiji said. What the Prime Minister said was that the Government has an open mind to consider all aspects of the situation; it also includes integration and it also includes separation....

SHRI MAHAVIR TYAGI: That was what I meant.

SHRI UMASHANKAR DIKSHIT: The purpose is to meet the situation. The situation can be met by removing the misunderstandings and the misinterpretations that were created. If the basic reason behind the agitation was met, the misgivings could be removed. Nothing has happened after the announcement of the Supreme Court judgment on Mulki Rules to change the situation, so far as the basic merits of the question of separation or integration are concerned. Sir, the main requirement is that there should be a meeting of minds, that there should be an open mind on both sides, to be ready to come without conditions. And that is the effort we have been consistently engaged in ever since the situation took an ugly and explosive turn.

Now, Sir, it has been said that it was wrong of the Prime Minister to criminalize the demand for the constitution of a new States Reorganization Commission. Now, let us first consider the situation in Andhra Pradesh.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: She could have said that the Government did not agree with this. But to say that it was an 'irresponsible' thing...

SHRI UMASHANKAR DIKSHIT: Let us understand what is meant by 'responsible' and 'irresponsible'. If a demand is publicly voiced which aggravates the situation, which might open floodgates of disturbances, which will create new problems for the whole country—the Opposition as well as the Government—then we have to consider whether such a statement or such a demand is responsible or not.

Now, let us consider the Andhra Pradesh situation. Looking at the question of language, all the three regions or all the main regions speak the same language. There is a common mode of living, of food they eat, of dressing themselves, and so on. They have the same culture and language and traditions, inherited from ancient times. I do not know whether there is any basic aspect of life at all which distinguishes them so as to make them try to run away from each other. The basic cause of this first arisen on the Telangana 3 P.M. idea of separation having side and recently on the Andhra reion is of a historical character. Telangana people lived under the Nizam's rule for a number of years. When the two States were about to join the federation, naturally there was a certain amount of uncertainty in their minds as to whether the advantage of certain special provisions applicable only to the local people would continue. The Nizam had introduced the Mulki rules because he did not have that kind of a mass base which was necessary and for lack of which he offered the special concessions. These concessions have become a part of the thinking of the Telangana people.

If we want to consider the question rationally it is mainly—and there are people on both sides who have conceded this—a question of the rate of development. Now, Sir, I am willing to grant and I freely concede the point that some parts of Andhra Pradesh are not as well developed as the others. Some parts need much more development and progress than the others. Even on Andhra side there

[Shri Uma Shanker Dikshit]

are places in the Rayalaseema region the economic condition of which is perhaps worse than that of Telangana. You will agree, Sir, that this position can obtain and does obtain in many other States in the country. In the case of a country which has remained under foreign rule for over 200 years it is not proper to expect that the developmental level would be the same in all parts. So, if we were to say that because one region is less developed and the other is more developed in Andhra Pradesh and therefore they should break into two or three parts, then, Sir, we would be treading on a very dangerous ground.

What is the effect of a State breaking into two or three parts? Assets and liabilities are to be considered. They have to be divided. There are huge common projects involving hundreds of crores of rupees. How are you going to divide them? There are numerous problems of insoluble character and it would hardly be possible for the party leaders to resolve them within any reasonable time. I say this with full sense of responsibility.

An emotional upsurge took place and a new situation developed rapidly. When the leaders found that the people had reacted sharply and powerfully to the Mulk Rules Act, they diltted the people and allowed themselves to be led by the people. There is nothing wrong in it provided you keep the movement well within the bounds of constitutional framework and within the rule of law. In this case moreover the leaders were taken away by their own feelings, by their own emotional nature and by the sudden increase in their following of students, N.G.Os. and other people and they thought that they were riding the waves. Well, Sir, they have ridden the waves. I think it was quite human on their part that they exploited the situation. But what is involved in the situation is a very serious principle of the integrity of the country. I do not say that a small State is necessarily wrong or that a large State is bad. It is all a question of what, in a given situation, is suit-

able. For instance, there are certain well-known principles which should govern the formation of a new State. At the States Reorganisation Commission's time the terms of reference required that in the first place, linguistic unity should be considered. Language and culture and unity of a people has to be considered. Then the economic viability has to be considered. Administrative feasibility has to be taken into consideration. And then, it has to be seen whether irrigation, water will be available, whether power can be created.

There are a number of important considerations which we must take into account if we want to develop the region, develop it into a progressive and prosperous State. It is not merely a question of administration; any State with a certain amount of funds can be run, but this is not the principle for which we stand. We are committed to social justice, to rapid development, to prosperity of the people, to equality of opportunity to various regions, to give special help and special opportunity of development to backward regions, backward districts all over the country. Friends who have read the approach to the Fifth Five Year Plan would have noted how nearly two-thirds of the total number of districts in the country have been chosen for special treatment from the developmental point of view.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: Is it outside administration—what you are telling? You have said “not only on administrative basis”. I say, is it something other than that?

SHRI UMASHANKAR DIKSHIT: My hon. friend is free to draw his own conclusions.

This is another point: I was a witness to the scenes when the first States Reorganisation Commission travelled from State to State. A few days before the arrival of the members of the Commission, there used to be general

issued

disturbances all over the place with flags and buntings, processions and demonstrations and serious police arrangements to control the situation. Do we want that to happen again? Now, the Commission consisted of very able and talented people. They were given a basic approach which was accepted by the entire country at that time; nobody was opposed to it. On that basis certain recommendations were made and the States were reorganised accordingly. Now, do we want to open a Pandora's Box again? I may make it clear without any fear of contradiction that if such a Commission is again announced, it might tantamount to a general invitation to the various regions and sub-regions to project their own demands. There are people in the various States; there are leaders and leaders; there are legitimate aspirations and other kinds of aspirations. There is some attraction in the idea that if States are divided there will be more Ministers and Chief Ministers, more High Courts and judges and Chief Secretaries and Secretaries; more of this and more of that. Are we going to encourage this kind of aspirations in our people and is it going to stop there? ... (Inter-ruption) ... The point that I was making is obvious to anybody who will try to understand. I did not intend originally to enter into any argument or try to answer the points of view that generally can arise or might arise in the course of further discussion. I merely wanted to explain the main basis of the decision to introduce President's Rule and I say I repeat, that it was not only constitutionally proper and necessary but it was inevitable. The decision has been fully understood in the country and it has been vindicated. It has been vindicated by the improvement in the situation, though it is gradual, that has taken place during the recent weeks. This, I hope, will provide an opportunity to all concerned to meet and find a rationale and a durable solution.

With these words, I move this Resolution and commend it to the unanimous acceptance of the House.

The questions were proposed

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I listened to our Home Minister's speech—rather his maiden speech as Home Minister—throwing light on the Andhra issue. Sir, for sometime our Prime Minister has been saying that she is keeping an open mind and when peace and calm prevails in Andhra, she will go into every aspect of the question, i.e. integration, bifurcation, etc. But, Sir, after listening to the Home Minister I have a suspicion that their mind is made up, that they would not consider the bifurcation aspect.

SHRI UMASHANKAR DIKSHIT: No, Sir. There is no question of making up of our mind.

SHRI S. S. MARISWAMY: I will be happy if the hon. Minister gets up and says that that is wrong but this is the impression I have got from his speech. The situation in Andhra is worse than that prevailing anywhere after the Independence of India. Never has violence been let loose as much as in Andhra. I have seen the military people, CRP people and the people who are in the police department running amuck in Andhra Pradesh. I should say that the situation today is worse than the Jalianwala Bagh. I am afraid the forces let loose by General Dyer would have been less dangerous than the CRP men at Guntur, Vijaywada and other places. I was told from a very reliable source that in Guntur 50 women belonging to respectable families went to the residence of the Superintendent of Police to present a petition, about the atrocities of the CRP people. The sentry posted at the residence of the S.P. asked them to sit in the verandah. While they were there, an urgent message was sent to the CRP people to corner them up. Those ladies were beaten and they were taken to get into an open lorry. The lorry was so high that these ladies could not climb up. So, some of the

[Shri S S Mariswamy]

lady homeguards who had been recently recruited pushed them by hair and threw them into the lorry. This has happened in Guntur.

SHRI N K SHEJWALKAR Shame, shame

SHRI S S MARISWAMY Also in Vijaywada there had been a ladies' procession and some doubtful characters who have been lately recruited by the police, were let loose amongst the group to beat them. Such of those ladies belonged to very respectable families. Sir, if this type of things goes on, I am really afraid where we are heading to.

I am equally interested in the integration of India and I am not for division of any part of the country but when a feeling is created, how do you see that their fears are allayed? How we approach the problems is the question now. Take the case of a man who has been taken into custody under the Internal Security Act in Hyderabad and he is put in jail. You know what his daily allowance is. If he is a mulki he gets Rs 7/50 and if he is a non-mulki from the Andhra area, Rayalaseema or Circar Districts I am told he is given Rs 4/50. Both of them are in the same cell, one man simply because he happens to be a Hyderabad man, a mulki, gets Rs 7/50 while the other man for the sin of having been born in some other area is to get only Rs 4/50. Certainly, Sir, I would say this is the worst kind of treatment that could ever be meted out to any citizen of this country.

SHRI V B RAJU (Andhra Pradesh) I think you were here when the Mulki Rules Bill was passed. The mulki rules apply for employment in the Government not for anybody else, not for rickshaw pullers or others.

SHRI K P SUBRAMANIA MENON (Kerala) But this is what is happening.

SHRI V B RAJU No, no

SHRI KOTA PUNNAIAH Whatever you are narrating, have we to take all these things as facts?

SHRI S S MARISWAMY These are facts that I have collected and I stand by these facts. If you can prove that these things are not correct I am ready to accept your version.

Now the States Reorganisation Commission was constituted in 1953. I believe in order to bring prosperity, unity and advancement to the people in the various regions as per the Resolution passed 25 years ago in the All India Congress Committee. After the Report came into being Andhra Pradesh was constituted with Hyderabad attached to it. Since that day until to-day that State has been ruled only by Congressmen, not even for a day a non-Congress Ministry was there. Whether it was Brahmananda Reddy, or Sanjeeva Reddy or Sanjeeviah, or anybody for that matter, continuously the Congressmen have been ruling that State. What have they been doing for the last 25 years? They have not done anything for their emotional integration. This phrase 'emotional integration' was coined by Panditji. They paid lip sympathy to it whenever they came outside Andhra Pradesh but they did nothing to achieve it. For the information of the House I would like to point out here that there was a small region which was a part of Kerala State. That was Kanyakumari District and it was attached to Madras in the year 1954. Here the Home Minister talked so much about the similarity between Andhras and the Mulkis, their mode of living, their food habits, their culture etc. But if you look at the culture of mode of living of the people of Nannai Nadu, that is, Kanyakumari, and that of the people of Madras you will find that there is a little difference. The people of Kanyakumari are more akin to Kerala State than to Madras. Even though they speak Tamil, their accent is a little different. It will be more Malayalam-Tamil than actual Tamil. But with all that

there has not been even a single case of friction there because whosoever ruled Madras State took the care to see that that portion got really emotionally assimilated with Tamil Nadu. But that had not been done here. Now the Home Minister was saying that immediately after the last general election the Ministry under Narasimha Rao was working very well, that it embarked upon progressive policies etc. I would say your choice of Mr. Narasimha Rao is your first failure. He is the cause for all the troubles that we are having. As I said the other day, if there had been a man chosen—I do not mind whether he is from Andhra side or from Telengana—with mass backing and popular loyalty, things would not have come to this sad end. There is a tendency and that is what I am unable to understand. Of course, it is internal politics of the Congress party and I am not interested in it. I am interested in the welfare of Andhra State, which is my neighbouring State. Whatever you do inside the Congress party is no concern of mine, but whomsoever you appoint as the Chief Minister, you choose as the Chief Minister must be in a position to deliver the goods. I am very sorry that the choice of yours was totally wrong and it ended in a fiasco. The net result is that in Andhra Desh and Telengana the whole thing is in blood-bath.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh): Because they appointed the Chief Minister on their own.

SHRI MAN SINGH VARMA: All the appointed Chief Ministers will be discarded by the public gradually.

SHRI S. S. MARISWAMY: Now, Sir, I was very glad to hear from the Home Minister that things are settling down and there is peace and calm there. I want that Andhra should be as normal and calm as it was six months before, but let us not take it for granted that the feelings of the Andhras have died down. Much water has flowed under the bridge. Both

the Telengana and Andhra people have demanded unanimously in one voice bifurcation. If some attempt is made to scotch that feeling, I am afraid the future will be gloomy. There may be a lull on the front, but the feeling is deep rooted which I can see clearly. So, when the Government of India takes up this question and is ready for a dialogue with the people, it should not totally rule out the possibility of bifurcation. It should take into account the real feelings of the real people of Andhra Pradesh and not of those people who are found around the Delhi secretariat and Parliament House. Thank you.

SHRI V. B. RAJU: Sir, I rise to support the Resolution moved by the Home Minister and, while doing so, I would like to place before this august House the facts and not merely satisfy myself with what I carry here from hearing. The hon. Member, Shri Shejwalkar, said that he had visited certain towns and he found that there was a persistent demand for the formation of a separate Andhra State. I do not want to enter into a controversy and dispute that point, because in the past seventeen years we had experienced in that area similar situations. I do not think Mr. Shejwalkar knew the incidents of 1955, 1956 and 1957. The whole trouble started from those years. In 1955 there was the States Reorganisation Commission recommending a separate State of Telengana. Mr. Papi Reddi was not in politics at that time. There was a lot of furor, as the hon. Home Minister put it.

SHRI BHUPESH GUPTA: (West Bengal): He is now in politics sitting in Rajya Sabha all right.

SHRI V. B. RAJU: The very fact that he is in this House means that he is in politics. This is a political institution. As the hon. Minister put it, when the Commission came, there was demonstration for Vishal Andhra and separate Telengana and to recall it I was beaten up because I asked for a

[Shri V B Raju]

bigger State I led a procession and thousands followed me. The States Reorganisation Commission for its own reasons and in its own wisdom, recommended for a separate State. I do not want to find fault with them. And based on that, there was a very effective demand for separate Telengana. And the Congress Working Committee constituted a four-man sub-committee consisting of Shri Dhebar, Shri Nehru, Shri Azad and Shri Govind Ballabh Pant. The committee sat for a long time and history records that Shri Azad took a very firm stand for separate Telengana but that Shri Pant held a different view, and Shri Nehru had to cast his preference. Sir, in the face of such a big agitation which moved the whole of Telengana area the erstwhile Hyderabad area, Shri Ramakrishna Rao, the then Chief Minister, could not address any meetings, the Home Minister, Shri Bindu could address meetings only with police protection. I was for 40 days in Delhi. After that, four people from Andhra and four people from Telengana entered into an agreement what is called a gentlemen's agreement. Hon. Members in the Opposition should realise that that gentlemen's agreement was signed by only eight people, Shri Gopala Reddy, Shri N. Sanjeeva Reddy, Shri A. S. Raju and G. Lachanna from Andhra and Shri Ranga Reddy, Shri Channa Reddy, Shri J. V. Narasinga Rao and Shri B. Ramakrishna Rao from Telengana, without consulting the people. After the signing of the agreement, there was no criticism there was nothing.

Sir, was it not a popular agitation? Was it not a feeling based actually on the sentiments at that time prevailing? Merely because some people agitated and very intensely, and extensively also should a big nation like ours immediately respond, doing it hurriedly and repenting at leisure? Should we do that?

The second thing that happened was, in 1969 I came into this House and I appealed, I carried the feelings

from there and I said that I was carrying the feelings of the people. I prayed for amending article 16(3) or if it was possible, to have a set up like that of Meghalaya to keep the integrity of the State somehow. But Parliament did not agree to it. Shri Shejwalkar at that time—I remember—oppose it. Shri Bhupesh Gupta spoke extensively and maintained a consistent stand and he put me a pertinent question as to what I stood for. Sir, the Telengana people placed their confidence in the Prime Minister, after two years of agitation left the matter to her to arbitrate and she agreed, and the Praja Samiti got merged in the Congress, went to the people in the Assembly elections got returned by a very substantial majority—70 out of 100 seats it won. What happened to that two-year agitation? How many lives were lost you know? More than the present number. One day 26 people were shot dead. On that evening, the Prime Minister flew from Delhi to Hyderabad, and everybody felt that Telengana was going to be constituted as a State. But we waited patiently. So the second onslaught on us also we were able to ward off, and we retained the integrity of the State.

Now the third one we are passing through. It is more than three months. What is the genesis of this? There was a reason for the Telengana agitation. Historical reasons were there. As I had said, the States Reorganisation Commission created that hope. And then there was that gentlemen's agreement which was not fully implemented. On January 19, 1969, leaders of all the political parties signed a statement in which it was agreed that injustice was done to Telengana. Even at that time, about four thousand employees of Andhra who were employed in Hyderabad against that Act, the Public Employment Act, they agreed to send them back, the Andhra leaders agreed to take them back. So much has happened. There was a reason for the Telengana movement,

there was a genuine cause for it. But ultimately, the people in Telengana, the leadership in Telengana, saw its wisdom in reconciling to keep the integrity of the State which safeguards the interests of Telengana. The whole basis of the integrity of the State with safeguards to the Telengana people's interests for historical reasons. And it was a transitory provision. And now what is this agitation for? Did the hon. Member who visited those towns put a question to anybody and find out why he was agitating? I think he has failed to do it. I must place before this House true facts....(Interruption by Shri N. K. Shejwalkar) I think I can carry conviction to you. I am sure my arguments stand on moral conviction. Sir in our state polity there are three wings which have the power to take decision—judiciary, executive and the legislature. In this particular case all the three wings have taken decision. Sir, if the people or a section of the people, however justified they may be, do not accept any of the decisions, what is the way out? We talk about the rule of law. We talk about democratic processes. The judiciary has validated the mulki rules. The head of the executive has said that justice will be done to both the areas. She gave a formula and Parliament enacted the law. Our Constitution does not provide a fourth alternative. Can the hon'ble Member show a fourth alternative? If that is possible, then we will consider the question afresh. Our Constitution has not provided for referendum. In fact, when in 1969 I came here I asked whether opinion poll could be taken as in Goa as was done by Shri Lal Bahadur Shastri. That was not accepted. We were told that it is not the best interests of the country. We accepted it. Opinion poll may not be in the interest of the country; it may not be possible. Our Constitution does not provide for it. That is one thing. The second thing is this is a simple matter, a very limited matter relating to services, a few services in the Secretariat. I do not know whether the

hon'ble Member had taken care to study the limited scope of the problem. There may not be any new employment at all in future in Andhra Pradesh because the government is over-employed. The Government has no money. On the other hand many have to be retrenched. Therefore, it is a limited matter relating to services.

Sir, the Supreme Court gave a decision. When the Supreme Court was hearing the case on the validity of Mulki Rules an advocate asked about the interpretation. It was not clear to him as to what was the implication of the validity of the Mulki Rules. In 1969 when the Supreme Court struck down the Employment Act, the advocate asked as to what would happen to the Mulki Rules, which were repealed by that Act. If the Supreme Court had taken realities into consideration and clarified the position, there would not have been any confusion. At that time it was doubted whether the Mulki Rules would survive. In 1972 also it did not say anything about the interpretation, the application of Mulki Rules. Now, as the hon'ble Minister of Home Affairs put it, what did the High Court say in the third round? I will read it out for the benefit of the House:—

"Mr. Justice S. Obul Reddi of the Andhra Pradesh High Court has held that the definition of 'Mulki' as appearing in Rule 1(B) read with Rule 3 does not apply to persons who are born in the erstwhile State of Hyderabad but to persons who come from an area outside the Telengana area or the Nizam's dominion, whether it be from Punjab, Kerala, Bengal or any other State in the country."

In view of this definition, has any person, including Mr. Papi Reddi, thought what they are fighting for. In fact, they are fighting for the abolition of the Mulki Rules. If this is the interpretation of a Mulki it is

[Shri V B Raju]

the Telengana people who should fight for the abolition of Mulki Rules. According to this definition Dr Chenna Reddy is not a Mulki, V B Raju is a Mulki. I came from outside. I was born in Andhra. I have settled there for 38 years. I have declared that I have no intention to go back, I am a Mulki. A person who comes from outside and has stayed for not less than 15 years and declares that he has no intention to go back is a Mulki. Where can Chenna Reddy go? He has no place to go back.

SHRI SANDA NARAYANAPPA (Andhra Pradesh) Mr Raju was quite right in saying that if this judgment had come earlier, this agitation would not have taken root. But the judgment came late.

SHRI V B RAJU I am only pointing out the genesis because I must place the true facts before the House. The hon Member Shri Shejwalkar had been there. Did he put any question to anybody, to any rickshaw-puller or any small grocery merchant or any cultivator or any agricultural labourer who constitute 80 per cent of the population, as to what this agitation is for and for whose interests it is carried on? Did he put this question? Sir, I do not want to take much time. This interpretation of 'Mu ki' came on the 15th February, 1973. This is the third stage. If a historian writes the history of Independent India and if a chapter is allotted to Andhra Pradesh, he will have to record how the Telugu-speaking people have been the victims of court decisions and what price they had to pay. The heaviest price we have paid for the court decisions. Sir, if this is the type of judgment from the highest judicial authorities in the country, if the courts do not look at realities but simply are satisfied with technicalities, the lives of millions of people are exposed to dangers. Sir, these judgments have not only affected the discipline in the services, but have destroyed the polity and the economy.

SHRI N JOSEPH (Andhra Pradesh) One question. Do you accept this interpretation?

SHRI V B RAJU There is no question of my accepting or your accepting. I am not a party there. I am a Telugu-speaking man, I am one of the 4½ crores of people. I am not accusing anybody or any section of people. I am a supporter of the policies and programmes of the Prime Minister in trying to deal with this situation very patiently, carefully, tactfully and to bring people to a dialogue and evolve a democratic process for finding a lasting solution for the area. I come from the area, I suffer. Mr Shejwalkar does not suffer. Sir, is it a code of the political parties to take advantage in such matters like separation, communal riots etc? In such matters, there must be no party approach. When did this agitation take root and develop like this? Only when the Opposition political parties, four parties, entered the arena and constituted the Andhra Mahasabha, Karyacharana Samiti and Sangarshan Samiti, involving the students. Then this movement picked up. Sir, I do not want that my neighbours should be affected. But I may warn them. Don't throw stones living in glass houses. I am requesting Mr Nijalingappa who is supporting the separatist movement, Mr Karunanidhi, who is supporting this movement.

SHRI S S MARISWAMY Sir, I take objection to this. Mr Karunanidhi or any DMK member did not advocate separation.

SHRI V B RAJU I am glad. Let not Mr Karunanidhi interfere in the internal quarrel of Andhra people.

SHRI S S MARISWAMY We have never done it.

SHRI V B RAJU If you are assuring us, I am very grateful to you. I am requesting Mr Vajpayee, the Jan Sangh Party, not to put his

little finger into it. It is very dangerous. I am requesting Mr. Piloo Mody also. He is a very intelligent man. He is a journalist. I am requesting him to leave the matter to the Telugu-speaking people to decide for themselves. They are going to decide for themselves. I am certain that when the passions cool down when things come to normalcy . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: As far as Mr. Piloo Mody is concerned, you need not take him seriously. He should start bifurcating himself.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON (Kerala): Sir, on a point of order. I would like to have a clarification from Mr. Raju. We are discussing in this Parliament which is constituted by the whole of India, a problem which concerns a part of India. Therefore, whatever may be the political opinions of different people, I do not think that Mr. Raju can say that Mr. Piloo Mody or Mr. Karunanidhi or somebody else has no right to interfere. Does he mean to say that only the Congress leaders have got the right to interfere?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is perfectly within his rights to give some suggestions.

SHRI V. B. RAJU: Those are not the words I used. I said there must be some code for political parties in communal matters, in matters affecting regions like this . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Piloo Mody, surely he admits, has a right to interfere; not only interfere but interfere with bulk.

SHRI V. B. RAJU: In these matters there must be a national approach. There shall not be a narrow political approach. That is all what I said. Nothing more, nothing less. I hope you will appreciate that.

SHRI S. S. MARISWAMY: Whatever you say is national and whatever the Opposition says is anti-national. Is that not what you mean?

SHRI V. B. RAJU: I leave it to the good judgment of the Opposition, whether it will be in the interests of the political parties themselves to do so. Anyhow, I am putting another question . . .

SHRI N. K. SHEJWALKAR: You are not doing anything . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shejwalkar, you had your say, Mr. Mariswamy had his say. It is not fair to interrupt another speaker.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: When he mentions certain names, what should be done?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He cannot voice your opinion.

SHRI V. B. RAJU: I am not saying anything unparliamentary. I am not saying anything personal against anybody. I am not saying anything of that type. It is a very critical phase through which we are passing. This agitation was started by the Government employees. It is purely a service matter. Mulki Rules refer only to Government employment; not to trade, not to commerce, not to labour, not to industry, not to anything else. Why are you objecting to this reservation? The reservation has been there for the last sixteen years—for twelve years under the Public Employment Act. In fact, in our Constitution we have got reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. For elective posts we have got reservations. For services we have got reservations. Even though the original provision was only for ten years, we extended it for another ten years. There is nothing wrong in making this reservation for a backward area but with understanding. The services have started this agitation. It would have been all right on their part if they had confined it to service matters. The service organisations have made the cause an issue for agitation for the break-up of the State. Are the Opposition parties prepared to surrender their prerogative to the service organisations for agitating for political issues?

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON:
You ask your Congressmen.

SHRI V. B. RAJU: These service organisations have made it an issue of the break-up of the State and the students are involved in it now.

For a discussion of the issue, normalcy must come first. There is definitely improvement in the situation. That violent activity is not there. Transport and communications which were interrupted have now resumed. But the main factor, the Government employees, who have been on strike for nearly 80 days and have been the cause of a lot of suffering of the people, they must come back to duty. Should not the Opposition cooperate with the Government? Should not they say a word about the Government employees and ask them to come back to duty? They have not said a word. Do they want to use service organisations for political ends? This is the question that has to be gone into. What is your policy? Should we use . . .

SHRI N. K. SHEJWALKAR: What has the Government done?

SHRI V. B. RAJU: They have said that the Government employees should come back to work. Their families are suffering. The non-Gazetted officers are on strike. They come from lower middle class and middle class families. Some of them have sold away whatever little jewellery they had with their wives, just to maintain themselves. This is the state of affairs there. I wish this House resolves and appeals to the NGOs to come back to duty. Even some Gazetted Officers have also gone on strike for some time. If indiscipline creeps into all other ranks, what will be the fate of democracy in this country? What was the political provocation? There was no political provocation at all. There was no political issue involved in this at all. Even for political power, for the office of Chief Minister, there was no quarrel between Telengana and Andhra. For that post from the beginning it was only Gopala Reddy

versus Sanjiva Reddy, Sanjiva Reddy versus Sanjivayya, Sanjivayya versus Brahamananda Reddy, all from Andhra. There was no political quarrel on the issue of power. Mr. Mariswamy was saying that there was some sort of a cultural difference. How does he say that? The man in Hindupur which is adjacent to Karnataka speaks Telugu. You know very well that a person living in Ichchapuram bordering Orissa speaks the same Telugu as others speak. You know that a person in Khammam speaks the same Telugu language as a person in the neighbouring district of Krishna. Why are you trying to draw lines of demarcation? Why do you want to divide the Telugu people? This is not relevant, whether it is a big State or small State. If Andhra Pradesh is to be divided on the ground that it is a big State, what about Madras? It is equally big. What about Mysore or even Bihar for that matter . . . (Interruptions) Then about backward areas and forward areas. This is the first case in India where a relatively developed and majority area is asking for separation. There was some justification if a minority and undeveloped or backward area had asked for separation. Here a relatively developed area is asking for separation . . .

SHRI MAHAVIR TYAGI: Let us be clear. Is your party in favour of division and separation or in favour of unity?

SHRI V. B. RAJU: After I spoke so much, does he get this impression? The point is simple. In my view the solution is not so important as the approach to the solution. The first point is whether the Government of India and Parliament should take a decision under threat of violence and strike by Government employees? First of all, normally should come and after that let us enter into some dialogue . . . (Interruptions). My desire is that Andhra Pradesh shall not be broken up. My desire is that there should be no second reorganisation Commission as it will only be inviting new troubles and diverting the attention of the

people to political issues instead of tackling the economic issues facing our country.

श्री बनारसी दास (उत्तर प्रदेश) उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्य का विषय है कि इस सदन में सविधान के आर्टिकल 356 के अनुसार आंध्र प्रदेश में प्रोक्लेशन के सबंध में हम लोग विवाद कर रहे हैं और आंध्र के अंदर आज कल प्रेसीडेंट का रूल है। आंध्र के अंदर जो वर्तमान परिस्थिति है वह सरकार की अदृष्टता, सरकार की एडहॉक नीतियाँ, दुर्लभ नीति और सरकार के अनिश्चय के ही कारण हैं। चेना रेड्डी केन्द्र के मंत्री थे। यदि दुर्भाग्य से वह डिसक्वालीफाई न हो जाते तो शायद 1969 में तेलगाना का कोई आंदोलन न होता और जो गवर्नमेंट इतना बड़ा मैसिस्व मैन्डेट का दावा करती है उस में इतनी क्षमता और साहस नहीं था कि डा० चेन्ना रेड्डी के खिलाफ अनुशासन सबंधी कोई कार्यवाही करती। लेकिन एक गठबंधन करने के लिए उन्होंने स्वयं आंध्र के अंदर रीजनलिज्म, सेपरेटिस्ट टेंडेन्सीज और क्षेत्रीय मनोवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया। वही डा० चेन्ना रेड्डी वहाँ के नेता बने हुए हैं और आज जो वहाँ के मुख्य मंत्री हैं उन की टैक्टलेसनेस के कारण आज यह सारी परिस्थिति वहाँ उत्पन्न हुई है। आज वे वहाँ पर किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं। अगर वहाँ श्री नरसिंह राव किसी के प्रति उत्तरदायी हैं तो केवल दिल्ली के प्रति उत्तरदायी हैं और इसीलिए हर वीक वे वहाँ पर सलाह लेने के लिए आते थे। यदि वहाँ का चीफ मिनिस्टर एक नामिनेटेड सूबेदार न होता और वहाँ की असेम्बली का सही प्रतिनिधि होता तो आज जो आंध्र में जनता जल रही है—पत्तो में निकला है कि दो अरब की संपत्ति का नुकसान हुआ है, वह न हुआ होता और मैं इस बात को मानता हूँ कि सरकार ने स्वयं हिंसात्मक प्रवृत्तियों को अपनी दुर्लभ नीति की वजह से प्रश्रय दिया।

आज लोगों की यह धारणा बन गई है कि शांतमय वातावरण में विचार-विमर्श के द्वारा किसी भी प्रश्न के ऊपर गौर नहीं किया जा सकता है, जब तक हिंसा नहीं होगी, जब तक विध्वसात्मक प्रवृत्तियाँ चरम सीमा पर नहीं पहुँचेंगी तब तक सरकार का आसन नहीं डोलेंगा। अरुणाचल में, नागालैन्ड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में यही हुआ और आसाम के कई टुकड़े कर दिये गए। पंजाब जो कि हमारी सीमा का एक प्रदेश था उसके 2 हिस्से कर दिए गए। आज भी कोई व्यक्ति यह नहीं जानता है कि आंध्र प्रदेश को नहीं विभाजित किया जाएगा। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो इस बात को मानते हैं कि स्टेट्स पर लड़ाई के जरिए से जो कोई फैसला होगा वह तमाम हिन्दुस्तान का विघटन करेगा और यहाँ की विश्व-स्तरीय प्रवृत्तियों को एक बार बल मिलेगा। लेकिन क्या कोई निश्चयपूर्वक कह सकता है कि प्रधान मंत्री फिर उन्हीं शक्तियों के सामने, राजनैतिक लक्ष्यों की पूर्ति की वजह से, नहीं झुक जाएंगे? आज इस बात का पूरी जनता के अंदर यकीन है। यू० पी० में मैं जानता हूँ, जो गवर्नमेंट कर्मचारी बर्खास्त किए गए, जिनका डिस्मिसल हाईकोर्ट से बहाल हुआ, यहाँ पर आपका ही चीफ मिनिस्टर आता है और वह उनको बहाल कर देता है। तो फिर वहाँ के कर्मचारी अपनी समस्याओं के लिए, अपने झगड़ों को निपटाने के लिए यदि डाइरेक्ट ऐक्शन का सहारा लेते हैं और तमाम नेशन को रैन्सम के लिए होल्ड करते हैं तो उसके लिए सिवाए गवर्नमेंट के और कौन दोषी हो सकता है। आज जब इस देश में हमारे सामने गरीबी और बेरोजगारी और विकास के प्रश्न हैं, जनता में विरोध का प्रश्न है, ऐसे में एस०आर०सी० की नियुक्ति करना फिर से पड़ारा बाक्स को खोलना होगा। कहीं न कहीं कोई फाइनलिटि होनी चाहिए और जहाँ तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, यह मौजूदा आंदोलन सरकार की डिल-मिल नीतियों का नतीजा है। ज्यादा अच्छा

[श्री बनारसी दास]

होता आन्ध्र एक रहता और एक रहना चाहिए। लेकिन उसकी हालत यह है कि तेलंगाना और आन्ध्र के दोनों अंगों का नेतृत्व जिनके हाथ में है उनको एक जगह बैठ कर इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वे एक जगह रह सकें। अब चूंकि सरकार ने स्वयं वह स्थिति पैदा कर दी है, पहले तेलंगाना में पैदा की और जब कि वहां पर आंदोलन चल रहा था उस वक्त तक सरकार शांत बैठी रही और बहुत देर के बाद फाइव प्वाइन्ट फार्मूला लेकर आई। उस वक्त तक आन्ध्र के अंदर आग लग चुकी थी। तो फिर वहां पर भीड़ के ऊपर गोली चलेगी, सम्पत्ति का ह्रास होगा, उसको रोका नहीं जा सकेगा तो आखिर उसका नतीजा क्या होगा? उसका कारण यह है, आन्ध्र की जनता जानती है, जैसे 1954 में सरकार झुकी—मैं उसे भूल समझता हूं, जैसे पंजाब का विभाजन हुआ, वह एक बड़ी भूल थी, उसी तरह से आसाम के कई हिस्से किए गए, यह भी एक बड़ी भूल थी—यह भी विभाजन की मांग छोटे से छोटे प्रदेशों की मांग, असंतुष्ट राजनैतिक नेताओं को संतुष्ट करने की मांग है। वे नेता लोग रिहैबिलिटेशन चाहते हैं। और अगर यही प्रकृति जोर पकड़ती रहे तो कुछ लोग आगे चलकर कहेंगे कि हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहां हो, नागालैन्ड का एक हो, केरल के अंदर एक हो। इस तरह से हिन्दुस्तान एक नहीं रह सकता। आज हम देखते हैं, कहीं गोदावरी वाटर्स का झगड़ा तय नहीं होता, कहीं नर्मदा वाटर्स का झगड़ा तय नहीं होता और इसी तरीके से कहीं पर गंगा के पानी का सवाल होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड का प्रश्न है। इन सब चीजों को लेकर, इस तरह की प्रवृत्तियों पर चलकर, यद्यपि हमारा देश एक है लेकिन क्षेत्रीय प्रवृत्तियां जो स्वराज्य के पहले दबी हुई थीं, चूंकि गांधी जी ने और जवाहरलाल जी ने हिन्दुस्तान को एक सूत्र में बांधा था और हम सब लोग एक सूत्र में एक देश की कल्पना

करते थे, हमारी निष्ठा एक देश के साथ थी, आज वह बिल्कुल राजनैतिक स्वार्थ, क्षुद्र मनोवृत्तियों को लेकर वातावरण को दूषित किया जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि हर जिला ही एक स्टेट होना चाहिए इस बात के लिए जोर दिया जाएगा। जनता को विश्वास में लेकर यह जानना चाहिए कि वह वास्तव में क्या चाहती है। वह दृढ़ता के साथ एक फैसला करे। यह सही है, स्ट्रीट्स में किसी मामले को ले जाने से कोई फैसला नहीं होता। आज गुंडागर्दी, मारकाट हो और कुछ थोड़े से गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स लाकर के कुछ झगड़ा पैदा करें, तो यह सब झगड़ा आगे चल कर जनता के हितों के विरुद्ध होगा।

लेकिन जैसे फाइव प्वाइन्ट फार्मूला और मुन्की रूल का मसला 1974 के अंदर खत्म हो जाते, तो फिर उनको 1976-77 तक ले जाना एक प्रकार से फिर से झगड़ा पैदा करना है। यह एक डिसक्रिमिनेटरी बात थी कि हैदराबाद में आन्ध्र के लोगों को एडमिशन न मिले, वहां पर लोगों को नौकरी न मिले। इस चीज का हल तो आर्थिक है और उसका हल प्लानिंग कमिशन के हाथ में है। अगर इस झगड़े में रायलसीमा को बिठला भी दिया जाय, तो कुछ समय बाद रायलसीमा का प्रश्न पैदा हो सकता है क्योंकि रायलसीमा का जो क्षेत्र है वह काफी बैकवर्ड है। इसलिए आज जरूरत इस चीज की है कि आन्ध्र में हिंसा, तोड़फोड़ की जो कार्यवाही हो रही है, जनता की सम्पत्ति का जो ह्रास किया गया है, उसका समर्थन कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये सब घटनाएं निन्दनीय हैं और इसके बारे में तब ही कोई फैसला किया जाना चाहिये जब कि वहां पर अच्छी तरह से शान्ति स्थापित हो जाय। यह प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और सब लोगों का फर्ज है कि अगर तेलंगाना और आन्ध्र के लोग एक जगह मिलकर और एक कुटुम्ब की हैसियत से रहना चाहते हैं, तो फिर इससे ज्यादा सौभाग्य की बात नहीं

होगी। लेकिन अगर तेलगाना और आन्ध्र के लोग दो अलग-अलग भागों में रहना चाहते हैं क्योंकि उनमें इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो गई है, वहाँ तर कुछ राजनीतिक स्वार्थ पैदा हो चुका है, इन सब दृष्टियों से उसका विभाजन आवश्यक हो जाता है, तो फिर इस कार्य में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन यह कार्य तब ही होना चाहिये जब वहाँ पर नार्मल कंडिशनस पैदा हो जाय, वहाँ का यातायात नार्मल हो जाय और सर्विसेज भी नार्मल कार्य में लग जावें। लेकिन मुझे खतरा इस बात का लगता है, जैसा कि अभी तक का अनुभव रहा है कि सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है। सरकार के सामने इस देश के नक्शे की कोई रूपरेखा नहीं है। सरकार इस बात की घोषणा नहीं कर सकती है कि उसका निश्चय अंतिम होगा।

सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये कि देश का जो प्रत्येक पिछड़ा हिस्सा है, देश का जो उपेक्षित वर्ग है उसके लिए वह पूरी तरह से प्रयास करेगी। वास्तव में देखा जाय जहाँ पर 40 प्रतिशत व्यक्ति पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, उसका किसी तरह से कोई भौगोलिक डिवाइजन करना न सम्भव है और न सम्भव हो सकता है। इसका तो एक ही तरीका है और वह यह है कि जो 40 प्रतिशत लोग पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, उनके लिए इस तरह की योजना बनाई जानी चाहिये ताकि वे भी दूसरे लोगों के बराबर आ सकें और उन लोगों को कम से कम जो जिन्दगी की बुनियादी जरूरत की चीजें हैं वे मिल सकें। सरकार को भी केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि एक बुनियादी दृष्टिकोण को अपने सामने रखना चाहिये, देश के हित को और देश की सुरक्षा को, देश के प्रशासकीय हित को और आर्थिक दृष्टि से इस प्रश्न का हल निकालना चाहिये। बारबार फिर से इन प्रश्नों को खड़ा करने से देश में एक अनिश्चितता की भावना पैदा करना है।

यह जो समस्या आज तेलंगाना और आन्ध्र के बीच पैदा हो गई है, वह स्वयं गवर्नमेंट की नीतियों का परिणाम है। यदि 1969 में ही दूरदर्शिता से ही इस चीज का सामना किया जाता तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। वहाँ पर सरकार ने स्वयं उन प्रवृत्तियों को उभारा और आज वह इसका परिणाम वहाँ पर देख रही है। इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल आज की परिस्थितियों में तब ही हो सकता है जब वहाँ पर पूरी तरह से शान्ति स्थापित हो जाये और शान्ति स्थापित होने के बाद दोनों भागों के लोगों की इच्छा पर इस प्रश्न को छोड़ दिया जाये। यदि वे एक जगह मिलकर रहना चाहते हैं, तो ठीक है। यदि नहीं रहना चाहते हैं, तो स्वेच्छा से, भाई की हैसियत से जैसे वे पहिले रहते थे, जिस तरह से हैदराबाद और आंध्र वाले अलग-अलग रहते थे, उस तरह से उनको रहने दिया जाये। विशाल आन्ध्र की तो एक भावनात्मक मांग थी जो उनकी कुछ समय के लिए पूरी हुई। उसके बाद वहाँ पर कुछ राजनीतिक नेताओं ने जो सकीर्ण भावनाएँ लिए हुए थे, पृथक रहने की मांग शुरू कर दी और इस तरह से उन लोगों ने पृथक भावना को इंजीनियर किया जिसकी वजह से आज सारा आन्ध्र जल रहा है।

मैं आशा करता हूँ कि यह जो प्रोव्लेशन जारी किया है, वहाँ शीघ्र समाप्त होगा और वहाँ पर ऐसी परिस्थिति पैदा होगी जिससे वहाँ परक आस्टोयूशन ठीक ढंग से काम करने लगे और शान्त वातावरण में फिर इस प्रश्न का हल किया जाय।

—

4 P.M.

Statement re: Damage to Chambal Bridge on National Highway No. 3 near Dholpur and suspension of Traffic on Delhi-Bombay National Highway

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Before the next speaker, Mr. Raj Bahadur wants to make a statement on the damage caused to Chambal Project.

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR: Sir, I place a copy on the Table of the House. It is about the damage to Chambal Project.

I. MOTION RE REVOCATION OF THE PROCLAMATION ISSUED BY THE PRESIDENT IN RELATION TO THE STATE OF ANDHRA PRADESH—contd.

II. GOVERNMENT RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF THE PROCLAMATION ISSUED BY THE PRESIDENT IN RELATION TO THE STATE OF ANDHRA PRADESH—contd.

SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Deputy Chairman, Sir, once again I rise to speak on the developments in Andhra Pradesh. Since I spoke last, happily some improvement in the situation has undoubtedly taken place. For this, our tributes go to the integrationists in Andhra Pradesh belonging to our party and also to some people belonging to the Congress Party who have been facing great difficulties in protecting their lives and properties in upholding the banner of unity, in opposing the sinister nature of the conspiracy behind that movement and in encountering the terror and violence which had been unleashed there with a view to forcing the Government of India to accept, to begin with, the separation of the State of Andhra Pradesh and then to proceed, if possible, under some pressures and violence, to put the entire question of the unity of the country in the melting pot. Sir, it is not accidental that synchronising with the separatist movement in Andhra Pradesh, the Jana Sangh Party, for example, has officially raised the slogan for appointment of a second States Reorganisation Commission. They want the Indian States to be reorganised into a larger number of States, say 30 to 40 or 40 to 50. They have even suggested that Uttar Pradesh should be

broken up into four separate States. Similar demands are coming up elsewhere also. Recently I was in Uttar Pradesh, the State of my friend, Mr. Dikshit. There Mr. Charan Singh, the defeated leader of the B.K.D., has raised the slogan that West U.P. should be separated from East U.P. B.K.D. is now stirring a separatist campaign and given the opportunity and chance and the secret reactionaries inside the Congress Party playing their part as they are doing in Andhra Pradesh, you may find that gentleman, Mr. Charan Singh, assuming the role of Uttar Pradesh B. V. Subba Reddy.

Sir, I find that the Swatantra Party has also come out in support of the demand for another series of reorganisation of states. Well, Mr. Piloo Mody is a new-comer to politics, but not a new-comer to reactionary ideas. In fact, he has been born and brought up in the cradle of reaction and big money. So, it goes as naturally as Godavari flows when he says that there should be reorganisation all over the country.

Then we have got our friends also in the Syndicate Congress. Mr. Morarji Desai was very much opposed to the reorganisation of the composite Bombay State, so much so that he had to risk his Chief Ministership. Once he went to Ahmedabad and he had to face what they call the people's curfew in the sense that nobody came to his meeting. Yet he was preaching the maintenance of composite Bombay State and would not concede the demand for linguistic reorganisation of the bi-lingual Bombay State. Now, here we find the officials. Even now they are ruled by them. The former ICS man, Mr. Iengar, has accused Nehru of vacillation because Nehru conceded the demands for linguistic reorganisation of the States. In a recent statement which he published in some Andhra paper, Mr. Iengar of the former ICS—also once Chairman of the Reserve Bank, I think—has demanded bifurcation of Andhra Pradesh. Then, we have got